



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 30—जुलाई 6, 2007 (आषाढ़ 9, 1929)

No. 26]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30—JULY 6, 2007 (ASHDHA 9, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .....	655	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	591	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .....	3	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ...	1011	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	3151
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .....	481
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .....	*	भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .....	10051
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ....	509
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	655	than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	591	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	3	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1011	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	3151
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....	481
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....	10051
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	509
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]  
 [Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 31 मई 2007

सं. ए-12018/1/2007-प्रशा. (अराज.)--मंत्रिमंडल सचिवालय अधिसूचना सं. 1/22/4/2007-कैब दिनांक 10 मई, 2007 के द्वारा लघु उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कर दिया गया है। एम.एस.एम.ई. मंत्रालय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए राज्यों के प्रयासों को अनुपूरित करने के लिए नीतियों और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों/योजनाओं के निर्माण, उनके कार्यान्वयन और संबद्ध समन्वयन हेतु नोडल मंत्रालय है। नए नाम और एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की जिम्मेदारियों को देखते हुए, सरकार ने विकास आयुक्त (लघु उद्योग) कार्यालय जिसे लघु उद्योग विकास संगठन भी कहा जाता है, का नाम बदलकर विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) कार्यालय करने का निर्णय किया है। विकास आयुक्त (एम.एस.एम.ई.) कार्यालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संबंध में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों/परियोजनाओं/योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन की निगरानी में सरकार की सहायता करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में काम करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को प्रेषित की जाए।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

प्रवीर कुमार,  
संयुक्त सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 मई 2007

विषय : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम--भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और समकक्ष और इससे ऊपर के पदों में भारतीय वन सेवा अधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए कार्यपद्धति।

सं. ए-12011/1/2003-भा.व.सेवा-1--उक्त विषय पर मूल परिपत्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के दिनांक 8 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन एफ-1.11/76-आईएफएस के तहत जारी किया गया था। परिपत्र में संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुदेशों को समय-समय पर जारी किया गया था। इन लागू सभी अनुदेशों की समीक्षा और इन्हें समेकित किया गया है, और अधोहस्ताक्षरी को विषय पर संबंधित सभी आदेशों के अधिक्रमण में सभी संबंधितों को सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित संप्रेषित करने का आदेश हुआ है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की

केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम

- 1) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय जिसे आगे से 'मंत्रालय' कहा जाएगा की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम जिसे आगे 'स्कीम' कहा जाएगा, 20 वर्षों से भी अधिक से चल रही है। इसमें मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकायों में आवधिक प्रतिनियुक्ति पदों जिसे गैर-केन्द्रीय स्टाफिंग पदों के नाम से जाना जाता है या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती से भरे गए पदों के अलावा केन्द्र में सहायक वन

महानिरीक्षक के या इससे ऊपर के अधिकारियों के चयन एवं नियुक्ति के लिए एक पद्धतिवार व्यवस्था का प्रावधान है। मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के पदों की नियुक्तियां भारतीय वन सेवा अधिकारी मांग कर की जाती है। सिद्धांत यह है कि इस प्रकार मांगे गए सभी अधिकारी भारत सरकार, जिसे इसके बाद केन्द्रीय सरकार या केन्द्र कहा जाएगा में प्रतिनियुक्ति पर एक निर्धारित अवधि के लिए सेवा करेंगे और बाद में वे अपने मूल संवर्ग में वापिस चले जाएंगे। उनकी प्रगति, विकास और पदोन्नति मुख्यतया अपने संवर्गों में होगी।

- 2) भारतीय वन सेवा के विभिन्न संवर्गों से वरिष्ठ स्तरों पर नई सूचनाओं के लिए ऐसी एक स्कीम का होना मंत्रालय की आवश्यकता है। यह सेवा संवर्ग और भारत सरकार के आपसी हितों का द्विमार्गी क्रियाकलाप है।
- 3) सामान्यता इस स्कीम के अंतर्गत शामिल पदों को राज्य/संयुक्त संवर्गों से भारतीय वन सेवा अधिकारियों को मांग कर निश्चित अवधि आधार पर भरा जाता है।
- 4) विशिष्ट मामलों में जहां विशिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए पर्याप्त संख्या में भारतीय वन सेवा अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 1966 के नियम 7(3) में उल्लिखित 'चयन सूची' में शामिल है राज्य वन सेवा के अधिकारियों को नियुक्ति के लिए चुना जा सकता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में पदों के मामले में राज्य वन सेवा के जिन अफसरों को अभी ऊपर उल्लिखित 'चयन सूची' में शामिल किया जाना है, भी विचार किया जा सकता है।

#### उद्देश्य :-

5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के क्षेत्र में निम्नलिखित मानक है :-

- i. भारत सरकार में सहायक वन महानिरीक्षक और इससे ऊपर के सभी पदों को भारतीय वन सेवा से निश्चित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पर भरा जा सकता है।
- ii. सेवा के राज्य/ संयुक्त संवर्गों में केन्द्र सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ पदों का प्रावधान है जिससे केन्द्र सरकार में पदों पर सेवा करने के लिए प्रशिक्षित और अनुभवी सदस्य मिलते हैं। तदनुसार विभिन्न राज्य संवर्गों के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कर्तों का उपयोग एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो उस स्तर को नियन्त्रित करता है जिससे सेवा के विभिन्न राज्य संवर्गों से अधिकारी मांगे जाते हैं।

## 2. पात्रता मानदण्ड

सहायक वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के पदों के लिए अधिकारियों की पात्रता नीचे दी गई है :-

पद नाम और वेतनमान	भारतीय वन सेवा में सेवाकाल के न्यूनतम वर्ष	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
सहायक वन महानिरीक्षक और समकक्ष i. सहायक वन महानिरीक्षक ग्रेड-II (10000-325-15200) ii. सहायक वन महानिरीक्षक-I (12000-375-16500) iii. वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (14300-400-18300)	7	अधिकारी वरिष्ठ समयमान या अधिक में मूलवेतन के रूप में कम से कम 10,975 रुपए आहरण कर रहे हों। इस स्तर पर पदों अर्थात् एआईजी श्रेणी-II, एआईजी ग्रेड-I और वरिष्ठ एआईजी जिनकी आर्हता सेवा क्रमशः 7, 9 और 13 वर्ष है, के मध्य कुछ छूट होगी।
उप वन महानिरीक्षक और समकक्ष (16400-500-20000)	15	अधिकारी 12000-16500 या इससे अधिक के वेतनमान में कम से कम 13775 रुपए मूल वेतन आहरण करता हो।
वन महानिरीक्षक और समकक्ष 18400-500-22400	19	18400-22400 रुपए के वेतनमान में किसी राज्य संवर्ग या सेवा के कम से कम एक अधिकारी की नियुक्ति आवंटन के उस वर्ष के अधिकारियों पर विचार करने के लिए पूर्व शर्त होगी।
महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण, निदेशक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी 22400-525-24500	26	मूल संवर्ग सेवा में 18400-22400 के वेतनमान में न्यूनतम 3 वर्षों सेवा और सेवा निवृत्ति के लिए न्यूनतम 2 वर्ष शेष होने चाहिए। योग्यता मानदण्ड समग्र बैच पर तब लागू होगा जब बैच का कोई अधिकारी 18400-22400 के मूल वेतन पद पर अपेक्षित 3 वर्षों की सेवा कर लेगा।
अपर वन महानिदेशक 24050-650-26000	29	मूल संवर्ग या सेवा में 18400-22400 के वेतनमान के पांच साल की सेवा और सेवानिवृत्ति के लिए न्यूनतम 2 वर्ष शेष होने चाहिए। योग्यता मानदण्ड समग्र

		बैच पर तब लागू होगा जब बैच का कोई अधिकारी 18,400-22,400 के मूल वेतन के पद पर अपेक्षित पांच वर्षों की सेवा कर लेगा।
वन महानिदेशक और विशेष सचिव 26000 रुपए (निश्चित)	30	24,050-650-26000 या इससे ऊपर के वेतनमान में अग्रनयन पद पर न्यूनतम 2 वर्षों की सेवा। योग्यता मानदण्ड समग्र बैच पर तब लागू होगा जब बैच का कोई अधिकारी 24050-650-26000 के मूल वेतन के पद पर अपेक्षित 2 वर्षों की सेवा कर लेगा।

**सहायक वन महानिरीक्षक और समकक्ष और उप वनमहानिरीक्षक और समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु संस्थानात्मक व्यवस्था**

- 7 सहायक वन महानिरीक्षक और उप वन महानिरीक्षक या समकक्ष रैंक के पदों को भरने के लिए मंत्रालय को इसके लिए गठित केन्द्रीय वानिकी स्थापना बोर्ड सहायता और परामर्श देगा। इस बोर्ड का गठन और कार्यों का विवरण नीचे दिए अनुसार है :-

- |      |  |   |                 |
|------|--|---|-----------------|
| i.   | सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय   | - | पदेन अध्यक्ष    |
| ii.  | सचिव, कार्मिक एवं शिक्षा विभाग   | - | पदेन सदस्य      |
| iii. | वन महानिदेशक और विशेष सचिव   | - | पदेन सदस्य      |
|      | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय   |   |                 |
| iv   | अपर वन महानिदेशक   | - | पदेन सदस्य      |
|      | पर्यावरण एवं वन मंत्रालय   |   |                 |
| v    | वन स्थापना अधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव या समकक्ष जो मंत्रालय में भारतीय वन सेवा संवर्ग प्रबंधन को देख रहा है। | - | पदेन सदस्य सचिव |

**बोर्ड के कार्य**

8. बोर्ड के यह कर्तव्य होंगे :-

- (क) विचार करने के लिए चयन के क्षेत्र में लाभों, अधिकारियों की योग्यता, और उपलब्धता के संबंध में सिफारिशें करना :

- i. मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत ए आई जी एफ और डीआईजीएफ या समकक्ष पदों पर नियुक्ति के लिए ।
- ii. अन्य पदों के लिए जिनका अधिकतम वेतनमान 20000 से अधिक नहीं है - जब सेवा के अधिकारियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव हो ।

(ख) अखिल भारतीय सेवा नियमावली जो कि बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है, के नियम 16(3) अंतर्गत है, समय पूर्व सेवा निवृत्ति के मामलों के संबंध में विचार करना और सक्षम प्राधिकरण को सिफारिशें करना और मुख्य वन संरक्षक के रैंक से नीचे/या समतुल्य अधिकारियों के बारे में संबंधित नियमों के अंतर्गत समयपूर्व सेवा निवृत्ति पर विचार करना ।

(ग) सरकार द्वारा इसे संदर्भित किए गए फैलोशिप प्रशिक्षण के ऐसे मामलों पर प्रतिनियुक्ति के लिए चयन पर सिफारिशें करना ।

**वन महानिरीक्षक एवं समकक्ष, महानिदेशक भारतीय वन सर्वेक्षण, निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और समकक्ष, अपर वन महानिदेशक और वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पदों पर नियुक्ति के चयन के लिए संस्थानात्मक प्रावधान**

9. वन महानिरीक्षक अथवा समकक्ष और अपर वन महानिदेशक स्तर सहित ऊपर के रैंक के पदों को भरने के लिए गठित विशेष चयन समिति, जिसे इसके बाद 'समिति' कहा गया है, मंत्रालय को मंत्रिमंडल की चयन समिति को सिफारिश करने की कार्रवाई करने में सहायता करेगी और सुझाव देगी ।

- |   |                |
|---|----------------|
| (i) सचिव,<br>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय                         | अध्यक्ष (पदेन) |
| (ii) सचिव<br>विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय                | सदस्य (पदेन)   |
| (iii) वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव<br>पर्यावरण एवं वन मंत्रालय | सदस्य (पदेन)   |

✽ वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए चयन मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की विशेष समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

- |                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| मंत्रिमंडल सचिव       | - | अध्यक्ष |
| गृह सचिव              | - | सदस्य   |
| सचिव(कार्मिक)         | - | सदस्य   |
| सचिव, पर्यावरण एवं वन | - | सदस्य   |

### विशेष चयन समिति के कार्य:-

1c. चयन पर विचार करने के लिए अधिकारियों की योग्यता पात्रता और उपलब्धता के संबंध में निम्न सिफारिशें करना :-

- (i) स्कीम के अंतर्गत वन महानिरीक्षक और समकक्ष/महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण/निदेशक, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वन एकादमी अथवा समकक्ष/अपर वन महानिरीक्षक/वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए।
- (ii) अन्य गैर सचिवालय पद जिनका अधिकतम वेतनमान 18,400 से कम न हो लेकिन 24,500 से अधिक न हो जब सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति प्रस्तावित की जाती है।

### वन स्थापना अधिकारी

11. स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय में भा0 व सेवा संवर्ग का प्रबंधन देखने वाले संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी को वन स्थापना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाएगा जिसे आगे से एफ ई ओ कहा जाएगा और वह विशेष चयन समिति का पदेन सचिव होगा।

एफ ई ओ के कर्तव्य इस प्रकार से होंगे :-

- (i) सी एफ ई बी/एस एस सी/ए सी सी के लिए सम्प्रेषण प्राप्त करना और उनके आदेशों को सम्बंधित अधिकारियों को प्रेषित करना
- (ii) एस एस सी/ सी एफ ई बी के कार्यक्षेत्र में पढ़ने वाली सभी संभव या समुपस्थित रिक्तियों के बारे में और ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अनिवार्य वरिष्ठता/योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारियों की उपलब्धता के बारे में अपने आपको सूचित रखना।
- (iii) केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पदों पर उपयुक्त अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पद्धतिबद्ध योजना के लिए राज्य सरकारों के साथ संपर्क बनाए रखना।
- (iv) सेवा के सभी संबंधित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीयता रिपोर्टों के उचित रखरखाव और अभिरक्षा को सुनिश्चित करना।
- (v) ए सी सी या सी एफ ई बी के कार्यक्षेत्र में नियुक्तियों के संबंध में अधिकारियों के चयन या प्रत्यावर्तन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार करना।
- (vi) व्यक्तिगत विकास सहित वरिष्ठ प्रबंधन (वन महानिरीक्षक और इससे अपर या समकक्ष) के सभी पहलुओं के बारे में अपने आप को सूचित रखना।



**स्वायत्त निकायों में नियुक्ति के लिए संवर्ग मंजूरी**

12. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित स्वायत्त निकाय मंत्रालय से संवर्ग स्वीकृति प्राप्त किए बिना किसी सदस्य की नियुक्ति नहीं करेगा।

**रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया**

13. प्रक्रिया इस प्रकार से होगी :-

- (i) विभिन्न स्तरों पर भारतीय वन सेवा अधिकारियों को उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/व्यक्तिगत आकलन रिपोर्टों डोजियर; सतर्कता निकासी और अन्य सेवा रिकार्डों के आधार पर नामिकागत किया जाएगा। वन महानिरीक्षक और इससे ऊपर के स्तरों पर पैनल के लिए सी सी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।
- (ii) विभिन्न ग्रेडों में नामिकागत अधिकारियों की सूची का एफ ई ओ द्वारा रखरखाव किया जाएगा।
- (iii) राज्य/संघशासित सरकारें नामिकागत अधिकारियों में से उन अधिकारियों के नाम प्रस्तुत करेंगी जिनको भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए भेज सकते हैं। ऐसे अधिकारियों की सूची "प्रस्ताव सूची" होगी।
- (iv) प्रत्याशित और वर्तमान रिक्तियों के बारे में राज्य/संघ शासित सरकारों को छमाही आधार पर अथवा उससे पहले, यदि ऐसी अपेक्षा हो, जानकारी दी जाएगी। इस सूचना को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।
- (v) स्क्रीनिंग समिति विशिष्ट पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :-

(क) वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के ग्रेड के पदों के लिए

1. वनमहानिरीक्षक और विशेष सचिव - अध्यक्ष
2. अपर वन महानिदेशक (एफ सी) - सदस्य
3. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) - सदस्य

(ख) उप वन महानिरीक्षक और उससे नीचे के पदों के लिए

- 1- अपर वन महानिदेशक (एफ सी) - सदस्य #
2. अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव) - सदस्य #
- 3 संयुक्त सचिव सदस्य

(# दोनों अपर वन महानिदेशक में से वरिष्ठ अध्यक्ष होगा)

एक विशिष्ट स्तर के अधिकारियों की स्क्रीनिंग के लिए उसी स्तर अथवा नीचे के स्तर का कोई अधिकारी स्क्रीनिंग समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए ।

- (vi) उम्मीदवारों के अंतिम चरण के लिए प्रस्ताव सूची/चयन किए गए प्रस्ताव सूची बोर्ड / समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
- (vii) 'पैनल' को कड़े चयन और ऐसे मानदण्डों के आकलन जैसे सेवाकाल, मैरिट, सक्षमता, नेतृत्व योग्यता के आधार पर नीति बनाने की क्षमता अनुभव और पद के लिए अधिकारी (अधिकारियों) की विशिष्ट उपयुक्तता के माध्यम से तैयार किया जाएगा ।
- (viii) उप वन महानिरीक्षक और समकक्ष स्तर के पदों पर नियुक्ति का अनुमोदन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा और वन महानिरीक्षक और उससे ऊपर के स्तरों के लिए ए सी सी द्वारा किया जाएगा । इस स्कीम के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित 'पैनल' उस मंत्रालय में उपयुक्त अधिकारी के चयन के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजा जाएगा ।
- (ix) किसी विशिष्ट पद के लिए 'पैनल' की वैधता सक्षम प्राधिकरण द्वारा इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी ।
- (x) एक बार नामिकागत (एमपैनलड) किया गया अधिकारी सेवानिवृत्ति तक नामिकागत रहेगा ।

### कार्यकाल

14(i) केन्द्र सरकार के अंतर्गत मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति का निर्धारित कार्यकाल स्कीम की मुख्य बात है । केन्द्र और राज्य और मुख्यालयों तथा फील्ड के बीच चक्रानुक्रम केन्द्र और राज्य सरकार के लिए नीति निर्माण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए व्यवहारिकता का एक निश्चित स्तर प्रदान करेगा । अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर, विभिन्न स्तरों पर प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल की अवधियां नीचे दिए अनुसार होंगी ।

ए आई जी एफ अथवा समकक्ष	- 4 वर्ष
डी आई जी एफ अथवा समकक्ष	- 5 वर्ष
आई जी एफ अथवा समकक्ष	- 5 वर्ष
आई जी एफ के स्तर के ऊपर	- 4 वर्ष

- 14(ii) वन महानिदेशक अथवा समकक्ष अधिकारी को जब स्कीम के अंतर्गत महानिदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण अथवा निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी अथवा समकक्ष स्तर पर नियुक्त किया जाता है तो उनका अधिकतम संयुक्त प्रतिनियुक्ति कार्यकाल सात वर्ष होगा । ए डी जी एफ के स्तर पर नियुक्ति के लिए संयुक्त कार्यकाल सात वर्ष का होगा । वन महानिदेशक और विशेष सचिव के पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होगा ।

- 14(iii) प्रतिनियुक्ति अवधि के पूरा होने की नियत तिथि पर प्रत्येक अधिकारी अपने मूल कार्यालय वापस भेजा जाएगा। तथापि अधिकारी के पास अपने निजी कारणों जैसे बच्चों की शिक्षा आदि के आधार पर अपने प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के पूरा होने की तिथि से पूर्व 31 मई तक अपने संवर्ग में वापस जाने का विकल्प है।
- 14(iv) स्कीम के अंतर्गत केन्द्र में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत अधिकारी को उसके द्वारा विदेश में लिए गए प्रशिक्षण की अवधि को केन्द्र में उसके कार्यकाल की गणना करते समय हटाया नहीं जाएगा।
- 14(v) भारत में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकारियों के मामले में केन्द्र में कार्यकाल की गणना के उद्देश्य से निम्नलिखित संस्थानों के मामले में प्रशिक्षण की पूर्ण अवधि को हटा दिया जाएगा।
- (i) राष्ट्रीय रक्षा कालेज, नई दिल्ली
  - (ii) रक्षा सेवाएं स्टाफ कालेज वेलिंगटन
  - (iii) राष्ट्रीय प्रबंध कार्यक्रम के लिए प्रबंध विकास संस्थान, गुड़गांव
- (iv) लोक प्रशासन में उन्नत व्यवसायिक कार्यक्रम पाठ्यक्रम के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान केन्द्र में केवल प्रथम कार्यकाल के लिए। यदि ए पी पी पी ए पाठ्यक्रम के लिए चयन प्रथम कार्यकाल के अंत में होता है तो अधिकारी का कार्यकाल पाठ्यक्रम पूरा होने तक बढ़ा दिया जाएगा।
- (v) डी ओ पी टी द्वारा प्रायोजित जन नीति पर एम बी ए पाठ्यक्रम के लिए भारतीय प्रबंध संस्थान बंगलौर
- (vi) जवाहर लाल नेहरू फेलोशिप के लिए चुने गए अधिकारी के लिए फेलोशिप पर व्यतीत केवल आधी अवधि ही केन्द्रीय कार्यकाल में गिनी जाएगी।
- 14(vi) इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी अधिकारी प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने के समय का अधिवार्षिता पर रिटायर्ड होने में एक वर्ष से कम समय रह गया हो तो वह चाहे तो सेवानिवृत्त कार्यकाल को अधिवार्षिता तक बढ़ा सकता है / और उसे मूल संवर्ग में वापस भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 14(vii) कोई अधिकारी जो निम्नलिखित संस्थानों/ पदों में से किसी पर भी कम से कम तीन वर्ष के लिए सेवारत रहा है उसे अधिकतम सात वर्षों के पूरे कार्यकाल की शर्त पर उस पद पर आधी अवधि को अपने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में जोड़ने की अनुमति दी जाएगी।
1. राज्य वन सेवा कालेज, बुरनीहाट, देहरादून और कोयम्बटूर
  2. पूर्वी वन रेंजर्स कालेज, कुर्सियांग
  3. शिलांग में मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय
  4. भारतीय वन सर्वेक्षण
  5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून

14(viii) विदेश में तैनाती अथवा विदेश सेवा से लौटने पर एक वर्ष से कम अवधि रह जाने पर अधिकारियों को उनके मूल संवर्गों में वापस भेज दिया जाए।

14 (ix) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत सेवारत अधिकारियों की समय से पूर्व उनके संबंधित संवर्ग में वापस मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुमत होगी।

(क) जब अधिकारी अपने संवर्ग में पदोन्नति का लाभ पाना चाहता हो।

(ख) जब अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का शेष कार्यकाल छह माह से कम हो

प्रतिनियुक्ति कार्यकाल पूरा होने से पहले संवर्ग में वापस लौटने के सभी मामलों के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का अनुमोदन अपेक्षित होगा। अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त होने से पहले अपने संवर्ग में वापस जाना 'बढ़ाया गया कूलिंग आफ' की शर्त पर होगा अर्थात् केन्द्र में अगली प्रतिनियुक्ति के लिए कूलिंग आफ को अधिकारी का सामान्य कार्यकाल पूरा होने (जब होना निश्चित था) की तारीख से गिना जाएगा।

14(x) पूर्व पैराग्राफों में यथा निर्धारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल प्रतिनियुक्ति पर बने रहने के लिए अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करते। केन्द्रीय सरकार के पास बिना कोई कारण बताए अधिकारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेजने अथवा उनकी तैनाती का स्थान बदलने का अधिकार सुरक्षित है। अधिकारियों के कार्यकाल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के विवेक से कम भी किया जा सकता है।

14 (xi) इस स्कीम के उपबंधों के अंतर्गत पद पर नियुक्त प्रत्येक अधिकारी को कार्यकाल पूरा होने पर मूल राज्य / संयुक्त संवर्ग में वापस भेजा जाएगा। अनुमोदित कार्यकाल पूरा होने पर संगठन/संस्थान का अध्यक्ष अधिकारी को कार्यमुक्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। किसी भी अधिकारी को अनुमोदित कार्यकाल के बाद संगठन/संस्थान में नहीं रखा जाएगा। रिक्त पद पर अस्थायी व्यवस्था के लिए ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकरण का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

14(xii) केन्द्र से कार्यकाल पूरा होने के बाद वापस आए अधिकारी को संबंधित संगठन/संस्थान दो माह तक की छुट्टी की अनुमति दे सकता है। और आगे अपेक्षित छुट्टी यदि कोई हो, की मंजूरी के लिए अधिकारी अपने मूल संवर्ग को आवेदन करेगा।

### विदेश में नियुक्ति से लौटने वाले अधिकारी

15. कोई अधिकारी जो दो वर्ष अथवा अधिक अवधि के लिए विदेश में नियुक्ति पर हो उसे विदेश में ऐसी प्रतिनियुक्ति से लौटने तक उसे नामिकागत किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा।

### केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर तैनाती के बीच अंतराल

16(i) किसी अधिकारी की केन्द्र सरकार में ए आई जी एफ, डी आई जी एफ, अथवा आई जी एफ के पद पर प्रतिनियुक्ति के लिए केवल तभी विचार किया जाएगा जब कि उन्होंने केन्द्र में अपनी नियुक्ति की प्रस्तावित तारीख को राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश सरकार अथवा अपने मूल संवर्ग

में तीन वर्ष की सेवा की हो। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीपसमूह, जम्मू और कश्मीर और सिक्किम जैसे राज्यों के मामले में निर्धारित अंतराल, जिसे "कूलिंग ऑफ" अवधि भी कहा जाता है, दो वर्ष का होगा। महानिदेशक, एफ एस आई/ निदेशक, आई जी एन एफ ए अथवा ए डी जी एफ अथवा समकक्ष स्तर की नियुक्ति के लिए "कूलिंग आफ" की अवधि एक वर्ष होगी। डी जी एफ अथवा एस एस के पद पर नियुक्ति के लिए कोई प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

- 16(ii) केन्द्र में प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने पर किसी अधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार से ली गई छुट्टी "कूलिंग आफ" अवधि में नहीं गिनी जाएगी। दूसरे शब्दों में "कूलिंग आफ" अधिकारी द्वारा राज्य सरकार, संघ शासित प्रशासन अथवा संवर्ग प्राधिकरण में ड्यूटी के रिपोर्ट करने से शुरू होगा।
- 16(iii) पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के अलावा अन्य संवर्ग के अधिकारियों के लिए "कूलिंग आफ" की अवधि, जिन्होंने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में सेवा करने का विकल्प दिया हो, अन्य के लिए निर्धारित "कूलिंग आफ" की सामान्य अवधि 50% कम कर दी जाएगी। (ऐसे अधिकारियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर में की गई सेवा को "कूलिंग आफ" में गिना जाएगा)।
- 16(iv) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सामान्यतया अंतर संवर्ग प्रतिनियुक्ति के अनुसरण में नहीं होगी। यद्यपि इसकी अनुमति केवल उन अधिकारियों के मामले में होगी जो पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू और कश्मीर के अलावा दूसरे संवर्ग के हैं और जिन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों अथवा जम्मू कश्मीर में कम से कम डेढ़ वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सेवा की हो।

### अनिवार्य प्रतीक्षा

- 17(i) यदि किसी अधिकारी को प्रशिक्षण से लौटने अथवा पद समाप्त होने आदि के बाद पूर्व में धारित पद से भिन्न पद पर नियुक्त किया जाता है तो वह पूर्व में धारित पद जिस पर वह पहले तैनात थे और उसी संगठन की स्थापना पर बने रहेंगे तथा उनके वेतन एवं भत्तों का वहन भी उसी संगठन द्वारा किया जाएगा जब तक कि वह नए पद पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते हैं। अनिवार्य प्रतीक्षा की अवधि के दौरान ऐसे अधिकारी की सेवा का मंत्रालय द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
- 17(ii) आवासीय आयुक्त अथवा 14.10.1983 से दिल्ली में राज्य सरकार में ऐसे ही समान पद पर तैनात अधिकारी को केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए विचार करते समय कम महत्व दिया जाएगा।

### रोक लगना

- 18(i) किसी अधिकारी को केन्द्रीय सरकार के आदेश के अनुसरण में सौंपे गए कार्यभार को ग्रहण करने में असफल होने और संवर्ग प्राधिकरण/ राज्य सरकार द्वारा विशेष समिति / सी एफ ई बी

द्वारा तैनाती के लिए "पैनल" में उनका नाम शामिल करने से पूर्व "प्रस्ताव सूची" से नाम वापिस लेने का अनुरोध न किया हो तो उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए सामान्यतया केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर आगे रोक लगा दी जाएगी।

- 18(ii) रोक लगाए जाने के विरुद्ध प्रतिवेदन पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा विचार किया जाएगा और निर्णय लिया जाएगा।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सैन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम और अन्य मंत्रालय की गैर सैन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम पदों पर नियुक्त अधिकारियों का संचालन

- 19(i) मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत शामिल पद पर नियुक्त अधिकारी की केन्द्र के दूसरे पद पर संचालन की अनुमति है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत शामिल पदपर अधिकारी की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अन्य मंत्रालय के गैर सैन्ट्रल स्टाफिंग स्कीम में विपरीत संचालन को भी अनुमति है।
- 19(ii) केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम और गैर-स्टाफिंग स्कीम में लगातार कार्यकाल की अधिकतम अवधि सात वर्ष होगी।

मामले जो स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

20. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित मामले जो इस स्कीम के अंतर्गत विशेष रूप से शामिल नहीं हैं उन पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम में अपनाई जा रही प्रक्रिया/मार्गनिर्देश लागू होंगे।

#### निरस्त करना और बचत

- 21 इस संशोधित स्कीम के लागू होने की तारीख से इस स्कीम के कार्य क्षेत्र में आने वाले विभिन्न पदों पर नियुक्तियों के लिए बनाए गए पुराने नियम के लागू होने पर रोक लगा दी जाएगी।

22. इन अनुदेशों के भाषांतर के संबंध में शंका अथवा विवाद का मुद्दा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को अंतिम निर्णय के लिए भेजा जाएगा।

जी. बालाचन्द्रन  
वन स्थापना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2007

सं. एफ. 9-65/2006-यू.3(ए).—

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने का अधिकार प्राप्त है;

2. और जबकि महर्षि मारकण्डेश्वर शिक्षा न्यास ने केन्द्र सरकार से अपने द्वारा संचालित 10 उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को 'महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय' के नाम एवं शैली में सम-विश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन किया था;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 21 मई, 2007 के अपने अनुशंसा पत्र द्वारा महर्षि मारकण्डेश्वर शिक्षा न्यास को 'महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय' के नाम एवं शैली के रूप में सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की सिफारिश की है;

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा 'महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय', मुलाना-अम्बाला (हरियाणा), जिसमें नीचे उल्लिखित शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं, को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नीचे उल्लिखित संस्थाओं द्वारा अपने आप को संबंधित सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय अर्थात् कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, हरियाणा से असम्बद्ध होने की तारीख से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है:

- (i) एम.एम. इंजीनियरिंग कालेज, मुलाना, अम्बाला;
- (ii) एम.एम. कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं बिजनेस प्रबंधन संस्थान, मुलाना, अम्बाला;
- (iii) एम.एम. दन्त विज्ञान एवं अनुसंधान कालेज, मुलाना, अम्बाला;
- (iv) एम.एम. फिजियोथेरेपी एवं पुनर्वास संस्थान, मुलाना, अम्बाला;
- (v) एम.एम. कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी एवं बिजनेस प्रबंधन (होटल प्रबंधन) संस्थान, मुलाना, अम्बाला;
- (vi) एम.एम. चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, मुलाना, अम्बाला;
- (vii) एम.एम. प्रबंधन संस्थान, मुलाना, अम्बाला;
- (viii) एम.एम. नर्सिंग कालेज, मुलाना, अम्बाला;
- (ix) एम.एम. फार्मसी कालेज, मुलाना, अम्बाला; और
- (x) एम.एम. चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान नर्सिंग कालेज संस्थान, मुलाना, अम्बाला;

(5) उपरोक्त पैरा 4 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठंकन की क्रम संख्या 8 में उल्लिखित शर्तों के भी अधीन है।

(6) भारत सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय अथवा इसकी किसी संघटक इकाई को कोई योजनागत अथवा योजनेतर अनुदान नहीं देंगे।

रवि माथुर  
संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF MICRO, SMALL &amp; MEDIUM ENTERPRISES

## RESOLUTION

New Delhi, the 31st May 2007

No. A-12018/1/2007-Admn.(NG).—The name of the Ministry of Small Scale Industries has been changed to Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises vide Cabinet Secretariat Notification No.1/22/4/2007-Cab. dated 10th May, 2007. The Ministry of MSME is the nodal Ministry for formulation of policies and Central Sector Programmes/Schemes, their implementation and related coordination, to supplement the efforts of the States for promotion and development of Micro, Small & Medium Enterprises in India. In keeping with the new name and responsibilities of the Ministry of MSME, the Government have decided to change the name of the Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), which is also known as Small Industry Development Organisation as Office of the Development Commissioner (Micro, Small & Medium Enterprises) with immediate effect. The Office of DC (MSME) would act as the Apex Body for assisting the Government in formulating and overseeing the implementation of its policies and programmes/projects/schemes in respect of Micro, Small & Medium Enterprises.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PRAVIR KUMAR

Jt. Secy.

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 9th May 2007

**Subject :** Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment and Forests — Procedure for selection and appointment of the Indian Forest Service (IFS) Officers to posts of and above the rank of Assistant Inspector General of Forests & equivalent in the Government of India.

No. A-12011/1/2003-IFS.I.—The basic circular on the above subject was issued vide Ministry of Environment and Forests' O.M. No. F.1.11/76-IFS of 8th January, 1984. Further instructions amending the circular were issued from time to time as approved by the Government. All these instructions in force have been reviewed and consolidated, and the undersigned is directed to communicate the following for the information and guidance of all concerned, in supersession of all relevant on the subject.

CENTRAL STAFFING SCHEME OF  
THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

- 1) The Central Staffing Scheme (CSS) hereinafter referred to as 'Scheme' of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) hereinafter referred to as 'Ministry' has been in operation now for over 20 years. It provides for a systematic arrangement for the selection and appointment of officers of and above the rank of Assistant Inspector General of Forests (AIGF) at the Centre, excluding the tenure deputation posts in the autonomous bodies under the Ministry, known as Non Central Staffing Scheme posts or posts filled by recruitment through the Union Public Service Commission. Appointments to all posts of the rank of Assistant Inspector General of Forests and above in the Government of India are made under the Scheme of the Ministry, by borrowing officers from the Indian Forest Service (IFS), the cardinal principle being that all officers so borrowed will serve the Government of India hereinafter referred to as Central Government or Centre, for a stipulated tenure on deputation and, thereafter, return to their parent cadres. Their growth, development and career prospects will be mainly in their own cadres.



- 2) The *raison d'être* of such a scheme is the Ministry's need for fresh inputs at senior levels from different cadres of the Indian Forest Service. This two-way movement is of mutual benefit to the Service cadres and the Government of India.
- 3) The posts included under this Scheme shall ordinarily be manned by Indian Forest Service (IFS) officers borne on State/Joint cadres borrowed on tenure basis.
- 4) In exceptional cases, where sufficient number of IFS officers are not available for appointment to specific posts, the officers borne on the State Forest Service (SFS) whose names are included in the 'Select List' referred to in Regulation 7(3) of the IFS (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, may be selected for appointment. In case of posts in the North Eastern Region, the SFS officers who are yet to be included in the 'Select List' referred to above, may also be considered.

#### **OBJECT**

5. The scope of the Central Staffing Scheme of MoEF is bound by the following parameters:-
  - (i) All posts of the rank of Assistant Inspector General of Forests and above in the Government of India may be filled on tenure deputation from the Indian Forest Service;
  - (ii) The States/Joint Cadres of the Service have a provision for Senior Posts under the Central Government, which provides for trained and experienced members of Service to serve on posts in the Central Government. Accordingly, utilization of the central deputation quota of different State cadres is an important factor governing the scale at which officers are borrowed from the various State cadres of the Service.

**ELIGIBILITY CRITERIA**

6. Eligibility of officers for holding posts of the level of Assistant Inspector General of Forests and above is as given below:-

Designation and pay scale	Minimum number of Years of Service in IFS	Remarks.
(1)	(2)	(3)
Assistant Inspector General of Forests (AIGF) and equivalent i. AIG Grade-II [Rs.10,000-325-15,200] ii. AIG Grade-I [Rs.12,000-375-16,500] iii. Senior AIG [Rs. 14,300-400-18,300]	7	Officers should be drawing at least of Rs.10,975 as basic pay in Senior Time Scale or more. The posts at this level will be operated flexibly between the levels of AIG Grade II, AIG Grade I and Senior AIG with the qualifying service being 7, 9 and 13 years respectively.
Deputy Inspector General of Forests (DIGF) and equivalent Rs.16,400-450-20,000	15	Officers should be drawing at least Rs.13,775 as basic pay in the pay scale of Rs.12,000-16,500 or above.
Inspector General of Forests (IGF) and equivalent Rs.18,400-500-22,400	19	Appointment of at least one officer of the Service of any State Cadre in the scale of Rs.18,400-22,400 would be a pre-condition for consideration of the officers of a particular year of allotment.
Director General, Forest Survey of India Director, Indira Gandhi National Forest Academy Rs.22,400-525-24,500	26	Minimum of three years of Service in the scale of 18,400-22,400 in the parent cadre or Service and a minimum of two years of Service left for retirement. Eligibility criteria will apply to the entire batch as soon as one officer of a batch has put in the required three years of Service on a post carrying basic pay of Rs.18,400-22,400.
Additional Director General of Forests (ADGF) Rs.24,050-650-26,000	29	Five years of Service in the scale of Rs.18,400-22,400 in the parent cadre or Service and a minimum of two years of Service left for retirement. Eligibility criteria will apply to the entire batch as soon as one officer of a batch has put in the required five years of Service on a post carrying basic pay of Rs.18,400-22,400.
Director General of Forests & Special Secretary (DGF & SS) Rs.26,000 (Fixed)	30	Minimum of two years of Service in a post carrying a basic pay of Rs.24,050-650-26,000 or above. Eligibility criteria will apply to the entire batch as soon as one officer of a batch has put in the required two years of Service on a post carrying basic pay of Rs.24,050-650-26,000.

**INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SELECTION FOR APPOINTMENTS TO POSTS AT THE LEVEL OF ASSISTANT INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (AIGF) AND EQUIVALENT AND DEPUTY INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (DIGF) AND EQUIVALENT**

7. For staffing posts of the rank of AIGF and DIGF or equivalent, the Ministry shall be assisted and advised by Central Forestry Establishment Board (CFEB) constituted therefor. The constitution and functions of this Board are as detailed below:-

**Constitution of the CFEB :**

- (i) Secretary, Ministry of Environment & Forests,  
- ex-officio Chairperson
- (ii) Secretary, Department of Personnel and Training  
- ex-officio Member
- (iii) The Director General of Forests & Special Secretary,  
Ministry of Environment and Forests - ex-officio Member
- (iv) Additional Director General of Forests,  
Ministry of Environment and Forests - ex-officio Member
- (v) Forest Establishment Officer i.e. Joint Secretary or  
equivalent, dealing with IFS cadre management in the  
Ministry  
-ex-officio Member Secretary

**Functions of the Board :**

8. It shall be the duty of the Board:-

- (a) to make recommendations, having regard to the merits, eligibility and availability of officers, in the fields of choice for consideration:
  - (i) for appointments to the posts of AIGF and DIGF or equivalent under the Central Staffing Scheme of the Ministry.
  - (ii) for appointments to other posts which carry a pay scale, the maximum of which does not exceed Rs.20,000/- when it is proposed to appoint officers of the Service.
- (b) to consider and make recommendations to the competent authority in respect of cases of pre-mature retirement under rule 16(3) of the All India Services (DCRB) Rules, as fall within the purview of Board and to consider premature retirement under relevant rules in respect of officers below the rank of Chief Conservator of Forests/ or equivalent.
- (c) to make recommendations for selection for deputation on fellowship training such of the cases as are referred to it by the Government.

**INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS FOR SELECTION FOR APPOINTMENTS TO POSTS OF INSPECTOR GENERAL OF FORESTS (IGF) & EQUIVALENT, DIRECTOR GENERAL, FOREST SURVEY OF INDIA (FSI), DIRECTOR, INDIRA GANDHI NATIONAL FOREST ACADEMY (IGNFA) AND EQUIVALENT, ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL OF FORESTS (ADGF) AND DIRECTOR GENERAL OF FORESTS & SPECIAL SECRETARY (DGF & SS):**

9. For staffing posts of the rank of IGF or equivalent and above upto and including the level of Additional DGF, the Ministry shall, in the process of making recommendations to the Appointments Committee of the Cabinet, be assisted and advised by a Special Selection Committee (SSC) constituted, herein after referred to as 'Committee'. The constitution and functions of the Special Selection Committee are detailed below :

- |       |  |                            |
|-------|--|----------------------------|
| (i)   | Secretary,<br>Ministry of Environment & Forests (MoEF)                                   | - Chairperson (Ex-officio) |
| (ii)  | Secretary,<br>Ministry of Science and Technology   | - Member Ex officio        |
| (iii) | Director General of Forests &<br>Special Secretary,<br>Ministry of Environment & Forests | - Member Ex officio        |

\* For appointment to the post of DGF & SS, selection shall be conducted by a Special Committee of Secretaries Under the Chairmanship of the Cabinet Secretary with the following composition:-

Cabinet Secretary	-	Chairman
Home Secretary	-	Member
Secretary (Personnel)	-	Member
Secretary Environment & Forests	-	Member

**Functions of the Special Selection Committee (SSC) :**

10. To make recommendations, having regard to the merits, eligibility and availability of the officers in the field of choice for consideration:
- (i) for appointments to the posts of IGF and equivalent/Director General, FSI/Director, IGNFA or equivalent/ ADGF/DGF & SS under the Scheme.
  - (ii) for appointments to other non-secretariat posts which carry a pay scale, the maximum of which is not less than Rs.18,400/-, but does not exceed Rs.24,500/- when it is proposed to appoint officers of the Service.

**FOREST ESTABLISHMENT OFFICER :**

11. Joint Secretary or equivalent dealing with the IFS cadre management in the Ministry shall be designated as the Forest Establishment Officer hereinafter called (FEO) under the Scheme and he would be the ex-officio Secretary to the SSC.

The duties of FEO *shall be* :-

- (i) To receive communications intended for the CFEB/SSC/ACC and to obtain and communicate their orders to the officers concerned.
- (ii) To keep himself informed of all possible or impending vacancies in the posts falling within the purview of the SSC/CFEB and the availability of officers of the requisite seniority/qualifications and experience for making such appointments.
- (iii) To keep himself in close touch with the State Governments, for the systematic planning for placement of suitable officers on deputation posts at the Centre;
- (iv) To ensure up-to-date maintenance and proper custody of the annual confidential records of all officers belonging to the Service;
- (v) To correspond with the State Governments in regard to the selection or reversion of officers in connection with the appointments within the purview of the ACC or CFEB;
- (vi) To keep himself fully informed of all aspects of senior management (i.e. IGF and above and their equivalent) including development of personnel for it.

**CADRE CLEARANCE FOR APPOINTMENT TO AUTONOMOUS BODIES**

12. The autonomous bodies wholly or substantially funded by the MoEF or any other Ministry shall not appoint a member of the Service without obtaining cadre clearance from the Ministry.

**PROCEDURE FOR FILLING UP OF VACANCIES :**

13. The procedure will be as under :-
- (i) The IFS officers at different levels shall be empanelled based on the evaluation of their Annual Confidential Reports (ACRs)/ Personal Appraisal Reports (PARs) Dossiers; Vigilance clearance and other Service Records. The Panels at the levels of IGF and above will require approval by the ACC.
  - (ii) The list of officers empanelled at different Grades shall be maintained with the FEO.
  - (iii) The State/UT Governments shall convey the names of the officers from amongst the empanelled officers whose services they are

willing to spare for deputation with the GOI. The list of such officers shall constitute the "Offer List".

- (iv) The anticipated and the existing vacancies shall be made known to the State/ UT Governments on six-monthly basis or earlier if so required. This information shall also be put on the Ministry's website.

- (v) A Screening Committee shall shortlist the suitable candidates for a particular post. The Committee shall comprise of

A. For the posts of the Grade of IGF and above:

- |    |           |   |          |
|----|-----------|---|----------|
| 1. | DGF & SS  | - | Chairman |
| 2. | ADGF (FC) | - | Member   |
| 3. | ADGF (WL) | - | Member   |

B. For the posts of the Grade of DIGF and below:

- |    |           |   |         |
|----|-----------|---|---------|
| 1. | ADGF (FC) | - | Member# |
| 2. | ADGF (WL) | - | Member# |
| 3. | JS        | - | Member  |

(# The senior of the two ADGFs would be the Chairman)

For screening of officers at a particular level, no officer of the same level or below shall be a Member of the Screening Committee:

- (vi) For final selection of the candidate the Offer List / Short-listed Offer List shall be put up before the Board/Committee.

- (vii) The preparation of a 'panel' shall be through a process of strict selection and evaluation of such criteria as length of the service, merit, competence, leadership, capacity for policy making on the basis of qualification, experience and specific suitability of the officer(s) to the post.

- (viii) The appointments to the posts up to the level of DIGF and equivalent shall be approved by the Ministry and for the level of IGF and above by the ACC. For appointments of officers under this scheme in other Ministries, a 'panel' approved by the competent authority in the MoEF would be forwarded to the concerned Ministry for selection of a suitable officer in that Ministry.

- (ix) The validity of a 'panel' for a particular post shall be for a period of one year from the date of its approval by the competent authority.

- (x) The officer once empanelled shall stay empanelled till retirement.

**TENURE**

- 14(i) The fixed tenure of deputation of posting under the Central Government in the Ministry is the heart of the Scheme. Rotation between the Centre and the States and headquarters and the field, provide a certain degree of pragmatism to the officers for policy formulation and implementation of programmes of the Central and the State Government. Based on the experience gained so far, the periods of tenure of deputation at the different levels shall be as under:-

AIGF or equivalent	-	4 years
DIGF or equivalent	-	5 years
IGF or equivalent	-	5 years
Above the level of IGF	-	4 years

- 14(ii) An officer holding the post of Inspector General of Forests or equivalent when appointed to a post under the Scheme at the level of Director General, Forest Survey of India (FSI) or Director, Indira Gandhi National Forest Academy (IGNFA) or equivalent shall have a maximum of seven years of combined deputation tenure. For appointment at the level of the ADGF, the combined tenure will be seven years. There shall be no fixed tenure for the post of the Director General of Forests and Special Secretary (DGF&SS).

- 14(iii) On the exact date of completion of deputation tenure, every officer shall revert back to his parent cadre. The Officer will, however, have a choice to revert to the cadre on the 31<sup>st</sup> May, previous to the date of the end of the deputation tenure in case of personal grounds such as children's education etc.

- 14(iv) The period of training abroad undergone by an officer, who was deputed while working at the Centre under the Scheme will not be excluded for the purpose of calculating the tenure at the Centre.

- 14(v) In cases of the officers who underwent training in India the complete period of training will be excluded for the purpose of calculating tenure at the Centre in the following institutions cases :

- (i) The National Defence College, New Delhi.
- (ii) The Defence Services Staff College, Wellington.
- (iii) The Management Development Institute, Gurgaon for the National Management Programme.
- (iv) The Indian Institute of Public Administration, New Delhi for the Advanced Professional Program in Public Administration (APPPA) course (only for the first tenure at the Centre). If the selection for the APPPA course is towards the end of the first tenure, the officer will get extension of tenure till the end of the course.
- (v) The Indian Institute of Management, Bangalore for MBA course on Public Policy sponsored by the DoPT.

- (vi) For an officer selected for the Jawahar Lal Nehru Fellowship, only half the period spent on the Fellowship will be counted towards the Central tenure.
- 14(vi) If an officer at the time of completion of his/her deputation tenure under this scheme has less than one year to retire on superannuation, can be given extension of tenure, if willing, till his/her superannuation and need not be reverted to the parent cadre.
- 14(vii) An officer who has served in any of the following institutions/posts for at least three years will be permitted to count half the period spent on that post towards his central deputation tenure, subject to a maximum overall tenure of seven years.
1. State Forest Service College, Burnihat, Dehradun and Coimbatore
  2. Eastern Forest Rangers College, Kurseong.
  3. Regional Office of the Ministry at Shillong
  4. Forest Survey of India.
  5. Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun.
- 14(viii) Officers left with balance tenure of less than a year on return from posting abroad or Foreign Service shall be reverted to their parent cadres.
- 14(ix) Premature reversion to the respective cadres of the Officers serving under the Central Staffing Scheme of MoEF may be allowed by the Cabinet Secretary:
- a. in cases where the officers want to avail the benefit of promotion in their cadres;
  - b. where the balance tenure of the officer is less than six months.
- All other cases of premature repatriation to cadres will require the approval of the Appointments Committee of the Cabinet. Officers reverting to their cadres prematurely shall be subject to the condition of 'extended colling off', viz, the cooling off for the next Central deputation being reckoned from the date the officers (were scheduled to) complete their normal tenures.
- 14(x) The deputation tenure as prescribed in the preceding paragraphs will not confer any right to the officers to remain on deputation. The Central Government reserves the right to revert the officers to their parent cadres at any time without assigning any reason or change his place of posting. The tenure of the officer(s) can also be curtailed in public interest at the discretion of the Competent Authority.
- 14(xi) Every officer appointed to the post under the provision of this Scheme shall revert to the parent State/Joint cadre on the completion of tenure. On completion of approved tenure, the Head of the organization/institute will be responsible for relieving the



officer. No officer will be retained in the organization/institute beyond the approved tenure. Temporary arrangements in vacant posts will require approval of the authority competent to make appointments in such posts.

- 14(xii) Officers on repatriation from the Centre on completion of tenure, may be allowed leave not exceeding two months by the concerned organization/institute. For sanction of further leave required, if any, the officer shall apply to the parent cadre

**OFFICERS RETURNING FROM FOREIGN ASSIGNMENT:**

15. An officer who has been on foreign assignment for a period of two years or more will not be considered for empanelment until he reverts back from such foreign deputation.

**INTERVAL BETWEEN POSTINGS ON DEPUTATIONS TO THE CENTRE:**

- 16(i) An officer will be considered for deputation to the Central Government on the posts of AIGF, DIGF, or IGF only if he has rendered three years of Service, prior to the proposed date of his appointment at the Centre, in the State Government/Union Territory Administration or in his parent cadre. In the case of the states like Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram, Andaman & Nicobar Islands, Lakshdweep Islands, Jammu & Kashmir and Sikkim the prescribed interval, also known as 'cooling off' period, will be two years. For appointments at the level of Director General, FSI/ Director, IGNFA or ADGF or equivalent, the period of 'cooling off' will be one year. No such restriction would apply for appointment to the post of DGF & SS.
- 16(ii) Any leave taken by the officer on completion of tenure of deputation at the Centre from the Central Government will not be counted towards 'cooling off' period. In other words, the 'cooling off' will count from the date the officer reports for duty to the State Government, Union Territory Administration or the cadre authority.
- 16(iii) The 'cooling off' period for the officers belonging to cadres other than North East and J&K, who opt to serve in the North Eastern States and Jammu & Kashmir after completing a spell of Central Deputation, will be reduced to 50 % of the normal 'cooling off' period prescribed for others. (The services rendered by such officers in the North Eastern States and Jammu & Kashmir will count towards 'cooling off')
- 16(iv) Central deputation will normally not be in continuation of inter cadre deputation. However, it can be allowed in case of officers who borne on cadres other than North Eastern States and Jammu and Kashmir who have served on Inter cadre deputation to North Eastern States or J&K for a minimum period of one and half years.

**COMPULSORY WAITING**

- 17(i) Where an officer is to be appointed to a post different from the one held previously on account of return from training, or abolition of post etc., he/she shall continue to be borne on the establishment of the organization in which he/she previously held the post and his/her pay and allowances shall be met by that organization, till such time he/she assumes charge of a new post. The services of such an officer during the period of his/her compulsory wait can be utilized by the Ministry, for any specific assignment.
- 17(ii) Officers posted as Resident Commissioners, or against similar posts of the State Governments in Delhi w.e.f. 4/10/1993 would get lower weightage when the Central Government considers their names for Central Deputation.

**DEBARMENT**

- 18(i) An officer will ordinarily be debarred for further Central deputation for a five years period, if he fails to take up an assignment in pursuance of an order of the Central Government and the cadre authority/State Govt. have not requested for withdrawal of the name from the 'offer list' before his name was included in the 'panel' by the Special Selection Committee/CFEB for a placement.
- 18(ii) A representation against debarment will be considered and decided by the Appointments Committee of the Cabinet.

**MOVEMENT OF OFFICERS APPOINTED UNDER THE CSS OF THE MoEF TO THE CSS OF THE DoPT AND THE NON-CSS POSTS OF OTHER MINISTRIES**

- 19(i) Movement of an officer appointed on a post included under Central Staffing Scheme of the Ministry to another post at the centre is permitted. Movement of an officer appointed on a post included under the Central Staffing Scheme of the MoEF to a non CSS of MoEF, DoPT, other Ministries and vice versa is also permitted.
- 19(ii) Maximum continuous tenure on the CSS and Non-CSS would be seven years.

**MATTERS NOT COVERED UNDER THE SCHEME:**

20. For the matters related to Central deputation that are not specifically covered under this scheme, the practice / guidelines being followed in the CSS of the DoPT would apply.

**REPEAL AND SAVINGS**

21. With effect from the date of coming into force of this amended Scheme, the old rules framed for appointment to various posts falling within the purview of this Scheme shall cease to operate.

22. Any issue in doubt or dispute regarding the interpretation of these instructions shall be referred to the Ministry of Environment & Forests for final decision.

G. BALACHANDHRAN

Forest Establishment Officer & Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 12th June 2007

No. F. 9-65/2006-U. 3(A).—

Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, any institution as deemed to be a university;

2. And whereas, Maharishi Markandeshwar Education Trust had applied to the Central Government to declare ten higher education institutions being run by them as deemed to be a university in the name and style of 'Maharishi Markandeshwar University';

3. And whereas, the University Grants Commission vide their recommendation dated the 21<sup>st</sup> May, 2007 have recommended the Maharishi Markandeshwar Education Trust as deemed-to-be-university in the name and style of Maharishi Markandeshwar University;

4. Therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), hereby declare 'Maharishi Markandeshwar University, Mullana-Ambala(Haryana), comprising the below-mentioned teaching institutions, as 'deerned-to-be-university', for the purpose of the aforesaid Act, with effect from the date on which all the below-mentioned institutions are disaffiliated from their affiliating university, viz., Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana:

- (i) M.M. Engineering College, Mullana, Ambala;
- (ii) M.M. Institute of Computer Technology & Business Management (MCA), Mullana, Ambala;
- (iii) M.M. College of Dental Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- (iv) M.M. Institute of Physiotherapy & Rehabilitation, Mullana, Ambala;
- (v) M.M. Institute of Computer Technology and Business Management (Hotel Management), Mullana, Ambala;
- (vi) M.M. Institute of Medical Sciences & Research, Mullana, Ambala;
- (vii) M.M. Institute of Management, Mullana, Ambala;
- (viii) M.M. College of Nursing, Mullana, Ambala;
- (ix) M.M. College of Pharmacy, Mullana, Ambala; and
- (x) M.M. Institute of Medical Sciences & Research Nursing College, Mullana, Ambala.

5. The declaration made in para 4 above is also subject to further conditions mentioned at Sr. No. 8 of the endorsement to this Notification.

6. Neither the Government of India nor the University Grants Commission shall provide any Plan and Non-Plan grant-in-aid to Maharishi Markandeshwar University or its constituent teaching units.

RAVI MATHUR  
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2007  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2007